

# मंजूरी : 73 स्वास्थ्य केंद्र होंगे अपग्रेड



प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 19 जुलाई. जगदीशपुर में हुई कैबिनेट में प्रदेश के 73 स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है. इन केंद्रों को अपग्रेड करने पर 776 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च होंगे. इन केंद्रों के लिए

नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग के पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है. निर्णय के तहत 29 उप स्वास्थ्य केंद्रों का अपग्रेडेशन 6-बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का अपग्रेडेशन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य

केंद्रों को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में और 7 संस्थाओं को 100 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा. इन संस्थाओं में 1600 नियमित एवं 71 संविदा के नवीन पदों के सृजन तथा कुल 560 व्यक्तियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस पर प्रति वर्ष 122.83 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

## इन विधेयकों को भी मिली मंजूरी

- मप्र निरसन विधेयक, 2026 .
- मप्र राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 .
- मप्र अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026 .
- मप्र निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 .
- मप्र ध्वंस्तरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 .
- मप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
- मप्र कोड ऑन एम्पावरिंग वर्कस्पेस, 2026 ,मप्र श्रम शक्ति सहिता 2026 .
- मप्र ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 .

## एम्स की तर्ज पर विकसित होगा जबलपुर मेडिकल कॉलेज

प्रदेश के चुनिंदा मेडिकल कॉलेजों को आने वाले दिनों में एम्स की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है . इसकी शुरुआत जबलपुर मेडिकल कॉलेज से हो रही है. कैबिनेट ने मप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है. इससे अब मेडिकल कॉलेज में उसी तरह की व्यवस्थाएं लागू होंगी, जो कि एम्स में लागू होती है .

## ई-बस से जगदीशपुर पहुंचे सीएम और मंत्री

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 19 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक के लिए ई-बस से जगदीशपुर पहुंचे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में ईंधन, शासकीय संसाधनों के मितव्ययी उपयोग और सुशासन की भावना को साकार करते हुए कैबिनेट के सदस्यों के साथ, सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री निवास से इलेक्ट्रिक बस से रवाना हुए.

मुख्यमंत्री ने इस अनुकरणीय पहल के लिए अपने शासकीय वाहन और सुरक्षा काफिला सीएम हाउस में ही छोड़े. समस्त मंत्रीगण और उनका स्टाफ प्रतः 10 बजे से मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां से तीन इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से



मुख्यमंत्री निवास से चली ई-बसों के प्रति राजधानी वासी विशेष रूप से उत्सुक रहे, कई स्थानों पर ई-बसों पर पुष्प वर्षा की गई. मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मार्ग में पातरा पुल, लांबाखेड़ा और जगदीशपुर में प्रवेश पर स्वागत किया गया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव के जगदीशपुर पहुंचने पर विधायक विष्णु खत्री ने अंग वस्त्रम से उनका स्वागत किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव का प्रवेश द्वार पर तिलक कर अभिवादन भी किया गया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर जगदीशपुर दुर्ग में लगाई गई धरोहर प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया।

सामूहिक रूप से सभी बैठक स्थल के लिए रवाना हुए. इस दौरान मंत्रियों के व्यक्तिगत वाहन,



# 10 साल पुराने प्रोजेक्ट की फाइल से धूल साफ, जबरन कॉलोनी होगी हॉफ

## नीलगंगा चौराहे से जूना अखाड़ा चौराहे तक सड़क होगी चौड़ी

### ठंडे बस्ते में थी फाइल

जानकारी के अनुसार, नीलगंगा चौराहे से जूना अखाड़ा चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण की योजना वर्षों पहले बनाई गई थी, बावजूद यह लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी थी। अब इस फाइल को दोबारा सक्रिय कर दिया गया है . नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम जल्द ही प्रभावित मकान मालिकों को नए सिरों से नोटिस जारी कर सकती है.

में जबरन कॉलोनी के 25 मकान चौड़ीकरण की जद में हैं. आवश्यकता पड़ने पर दूसरे चरण में अन्य मकानों को भी हटाया जा सकता है. इससे जबरन कॉलोनी के सामने से सड़क चौड़ीकरण का रास्ता पूरी तरह साफ होने की संभावना जताई जा रही है.

**पेशवाई और महाकाल मार्ग –**

यह मार्ग सिंहस्थ के दौरान अखाड़ों की पेशवाई का प्रमुख रास्ता है. इसी मार्ग से नानाखेड़ा और देवासगेट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कई स्कूल, कॉलेज, मंदिर तथा शहर के प्रमुख क्षेत्रों के लिए यातायात संचालित होता है. बढ़ते ट्रैफिक और सिंहस्थ-2028 को देखते हुए प्रशासन इस मार्ग को अधिक चौड़ा और सुगम बनाना चाहता है.

**पहले भी दिए थे नोटिस –**

बताया जा रहा है कि पूर्व में भी नीलगंगा चौराहे से जबरन कॉलोनी तक करीब 25 मकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे. उस समय कुछ रहवासियों ने स्वयं अतिक्रमण हटाने की सहमति भी जताई थी. नगर निगम द्वारा सड़क के बीचों-बीच चौड़ीकरण के निशान भी लगाए गए थे, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी.

**85 फीट की योजना –**

गौरतलब है कि सिंहस्थ-2016 के दौरान भी कई मकानों के सामने का लोगभग 10 से 12 फीट हिस्सा हटाया गया था. अब बढ़ती आबादी, श्रद्धालुओं की संख्या और भविष्य की यातायात जरूरतों को देखते हुए 85 फीट सड़क चौड़ीकरण की योजना पर फिर से तेजी से काम शुरू होने की संभावना है.

## एक नजर में जादूटोने के शक में वृद्ध महिला की हत्या

शहडोल. जिले की जयसिंहनगर पुलिस ने जादूटोने के शक में 70 वर्षीय एक वृद्ध महिला की हत्या करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है . पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल ने आज बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनिल यादव और सुनील यादव के रूप में हुई है. दोनों को संदेह था कि उनकी पड़ोसन तथा उनकी मौसी की सास गेंदा बाई यादव (70) तान्त्रिक क्रिया (जादूटोना) करती थीं, जिसके कारण उनके परिवार के सदस्य लगातार बीमार रहते हैं. उन्होंने बताया कि इसी अंधविश्वास के चलते दोनों आरोपियों ने वृद्ध महिला की हत्या कर दी.

## असंतुलित पदस्थापना से पढ़ाई प्रभावित

देवास. जिले में प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक अनेक शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी तथा असंतुलित पदस्थापना के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की शिकायत सामने आई है. जिला शिक्षा अधिकारी राजीव सूर्यवंशी ने स्वीकार किया कि जिले के कई विद्यालयों में शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप शिक्षकों की उपलब्धता नहीं है. नियमानुसार प्राथमिक विद्यालय में दो तथा माध्यमिक विद्यालय में तीन शिक्षकों की व्यवस्था होना चाहिए. कई स्थानों पर छात्र संख्या कम होने के कारण प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का संचालन एक साथ किया जा रहा है.

## रेलवे कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर

भोपाल, 19 जुलाई. रेलवे कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया.

रेलवे पॉलीक्लिनिक, हबीबगंज द्वारा आयोजित इस शिविर में 40 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लेकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया और विशेषज्ञ चिकित्सकों से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्राप्त किया.

शिविर के दौरान डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों ने कर्मचारियों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया. साथ ही उन्हें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी.

## नीट परीक्षा कमलनाथ ने की परीक्षा परिणाम की शिकायतों के तत्काल निराकरण की मांग

# मार्कशीट के अंकों में कथित असमानता

भोपाल, 19 जुलाई. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नीट परीक्षा परिणाम में ओएमआर शीट और मार्कशीट के अंकों में कथित असमानता सहित विभिन्न शिकायतों का तत्काल निराकरण करने की मांग की है.

कमलनाथ ने आज जारी बयान में कहा कि नीट परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर पिछले कई वर्षों से सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने कहा कि पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं और पूरा देश नीट परीक्षा में पारदर्शिता चाहता है.



उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि नीट परीक्षा परिणाम में ओएमआर शीट और मार्कशीट के अंकों में भारी असमानता सामने आई है.

कमलनाथ ने कहा कि सतर्कता के दावों के बावजूद परीक्षा परिणाम में इस प्रकार की कथित अनियमितताओं का सामने आना विंता का विषय है. उन्होंने कहा कि इससे परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं. उन्होंने मांग की कि परीक्षा परिणाम से संबंधित सभी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो.

इसके अलावा अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के तीन-चार घंटे के भीतर ही परिणाम घोषित किए जाने को लेकर भी अभ्यर्थियों ने शिकायतें की हैं.



अपव्यय राशि 3 लाख 15 हजार 805 रुपए, जनपद पंचायत मझौली में ठोंगा दानव पर्वत पर खेल विकास कार्य का कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में 15 लाख 98 हजार 314 रुपए अपव्यय राशि वसूली योग्य पाई गई। इसी तरह बिछिया, भमरहा रोड से घूमा मार्ग में 21 नग ड्रेनेज कार्य में अपव्यय राशि 2 लाख 37 हजार 501 रुपए, कोल्हूआ मुख्य मार्ग से जमतिहवा टोला तक पुल-पुलियों के निर्माण में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। राशि वसूली योग्य पाई गई। दुबरी से चित्रवाह मार्ग

## इनका कहना है ....

महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में भ्रष्ट इंजीनियरों की पोस्टिंग कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी। यदि गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यों से कोई दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और उनकी पोस्टिंग कराने वाले लोग होंगे। समय रहते जांच में दोषी पाए गए इंजीनियर की पोस्टिंग वृथक की जानी चाहिए।

– कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास

## दोष सिद्ध प्रभारी ईई की यहां हुई शिकायत

दोष सिद्ध प्रभारी ईई हिमांशु तिवारी की शिकायतकर्ता एएन सिंह सीधी द्वारा पूरे प्रमाण के साथ प्रमुख सचिव मप्र शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल, अपर मुख्य सचिव मप्र शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय निकास एवं आवास विभाग भोपाल, आयुक्त संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल, मुख्य अभियंता तकनीकी कार्यालय विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल, प्रमुख अभियंता मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल, आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन से शिकायत की गई है।

## नशीले कफ सिरप के साथ आरोपी गिरफ्तार

रिवा. प्रदेश व्यापी नशा विरोधी अभियान के दौरान चोरहटा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली. रात में थाना प्रभारी ने दलबल के साथ एक कार से 1052 शीशी नशीली कफ सिरप पकड़ने के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एवं म.प्र.ड्रग कंट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है. नशीली कफ सिरप आरोपी यूपी प्रयागराज से लेकर आ रहा था. चोरहटा थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात मुखबिर से सूचना मिली थी की एक कार में नशी की बड़ी खेप लाई जा रही है. सूचना के आधार पर करहिया रोड में घेराबंदी कर कार को पकड़ा गया.



और राजस्थान के 12 जिलों में खुले जंगलों में विचरण कर रहे हैं, जबकि अन्य बड़े बाड़ों में रखे गए हैं. बुलेटिन में बताया गया है कि फील्ड टीमें प्रतिदिन जंगल, पहाड़, नदी किनारों और कृषि क्षेत्रों में चीतों की लोकेशन ट्रैक करती हैं. गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और मानसून में उफनती नदियों के बीच भी निगरानी का कार्य लगातार जारी रहता है.

## जनता की आवाज को दबाने के बजाय उसे सुनें

सिंधार ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाने के बजाय उसे सुना जाना चाहिए. उन्होंने सरकार से दमन का रास्ता छोड़कर संवाद का मार्ग अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि जनहित और न्याय की इस लड़ाई में कांग्रेस प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है.

## बिजली के खंभे से टकराई कार, युवक की मौत

ग्वालियर, 19 जुलाई. डबरा-भितरवार रोड पर सड़क हादसे में 30 साल के मनीष गुर्जर की मौत हो गयी. पुलिस के अनुसार जवाहर वेयरहाउस के पास उनकी होंडा डब्ल्यूआर-वी कार बेकाबू होकर पहले बिजली के खंभे से टकराई और फिर सड़क किनारे पलट गयी.

गंभीर चोट लगने की वजह से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. मनीष गुर्जर पुत्र महेंद्रसिंह गुर्जर भितरवार के बाबा गांव के निवासी थे. वह अपनी होंडा कार से भितरवार से गांव लौट रहे थे. इस बीच डबरा-भितरवार रोड पर जवाहर वेयरहाउस के पास उनकी



कार बेकाबू हो गयी. कार पहले बिजली के पोल से टकराई और इसके बाद सड़क किनारे पलट गयी. दुर्घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी. मनीष की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी.

## पेज एक का शेष

## एमपी में सब एकसमान

कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ब्रीफिंग की. उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल 2026 को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें शिक्षाविद, विधि विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया. समिति ने प्रचलित कानूनों का विस्तृत

अध्ययन करने के साथ-साथ प्रदेशभर में जन-परामर्श बैठकें आयोजित कर विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त किए. जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल भी तैयार किया गया. इसके अतिरिक्त 3.49 करोड़ एसएमएस भेजे गए तथा जिला एवं राज्य स्तर पर 50 जन-परामर्श बैठकें आयोजित की गईं, जिनसे 1,134 से

अधिक सुझाव प्राप्त हुए. व्यापक जनसंवाद के दौरान लगभग 94 प्रतिशत लोगों ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने का समर्थन किया. सीएम ने बताया कि यूसीसी को 80 फीसदी मुस्लिम बहनों ने तो समर्थन देते हुए कहा कि इसे लागू होना चाहिए. वहीं 40 फीसदी मुस्लिम भाईयों ने भी कहा कि यूसीसी लागू होना चाहिए.

## सर्वदलीय बैठक के जरिए समन्वय बैठाने का प्रयास

जबकि सरकार राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक 2026 वंदे मातरम, आयकर संशोधन विधेयक 2026, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से 37 करने वाला संशोधन विधेयक 2026, विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026, एसएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, विकसित भारत शिक्षा अधिनियम विधेयक 2025 को पास कराने की तैयारी में है. हालांकि सरकार ने इस सत्र के एजेंडे से सबसे विवादित विधेयों जैसे 130वें और 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक ( परिसीमन और सार्वजनिक पद से हटाने) को फिलहाल बाहर रखा है, ताकि विधायी कामकाज बिना किसी बड़े संवैधानिक गतिरोध के आगे बढ़ सके. यानी उक्त दोनों महत्वाकांक्षी विधेयकों को सत्र के अंत में लाया जा सकता है.